

उत्तर प्रदेश में रक्षा मंत्रालय लगाएगा 250 मेगावाट क्षमती की सौर बिजली परियोजना

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

रक्षा मंत्रालय ने अपनी खाली पड़ी जमीन का उपयोग सौर ऊर्जा के लिए करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में 250 मेगावाट की सौर बिजली परियोजना लगाने का फैसला किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीतापुर के पूर्व छावनी क्षेत्र में रक्षा मंत्रालय की खाली पड़ी लगभग 850 एकड़ जमीन पर बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (बीईएसएस) सहित 250 मेगावाट की सौर बिजली परियोजना की स्थापना को मंजूरी दी है। रक्षा मंत्रालय द्वारा अपनी अतिरिक्त अनुपयोगी जमीन पर शुरू की गई यह अपनी तरह की पहली परियोजना है।

रक्षा मंत्रालय ने इस परियोजना को मंजूरी दिए जाने की मंगलवार को जानकारी साझा करते हुए कहा, सीतापुर में रक्षा भूमि पर एकीकृत बीईएसएस सहायता के साथ बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा उत्पादन सुविधा का विकास भी शामिल है। मंत्रालय का दावा है कि यह

► सीतापुर क्षेत्र में रक्षा विभाग की 850 एकड़ भूमि पर सौर ऊर्जा परियोजना को रक्षा मंत्री की मंजूरी

► रक्षा प्रतिष्ठानों की ऊर्जा सुरक्षा बढ़ेगी और बिजली खर्च में होगी कमी, एनटीपीसी संभालेगी प्रोजेक्ट



प्रतीकात्मक

पहल स्वच्छ ऊर्जा, सतत विकास और पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता कम करने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

सैन्य बलों के लिए दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के अलावा इस परियोजना से रक्षा प्रतिष्ठानों के लिए

पारंपरिक ग्रिड बिजली की खरीद पर होने वाले खर्च में कमी आने की उम्मीद है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार, इस परियोजना को सरकारी कंपनी एनटीपीसी कार्यान्वित कर रही है जो रक्षा प्रतिष्ठानों के लिए सबसे अनुकूल ऊर्जा मूल्य निर्धारण और बचत सुनिश्चित करने के लिए प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के जरिये चयनित की गई है। यह परियोजना रक्षा मंत्रालय (सेना) के एकीकृत मुख्यालय और रक्षा संपदा महानिदेशालय (डीजीडीई) के साथ समन्वय में कार्यान्वित की जाएगी। परियोजना पूरी होने पर सीतापुर सौर ऊर्जा परियोजना रक्षा भूमि पर स्थापित देश की सबसे महत्वपूर्ण नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में से एक के रूप में उभरेगी। इस परियोजना के रक्षा क्षेत्र में सौर-सह-भंडारण परियोजनाओं के लिए मानदंड स्थापित करने की उम्मीद है। यह परियोजना राष्ट्रीय सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, तकनीकी नवाचार व पर्यावरणीय स्थिरता का संगम ही नहीं रणनीतिक हितों की रक्षा करते हुए राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों के समर्थन में उसकी प्रतिबद्धता दर्शाता है।